



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 भाद्र 1944 (श10)

(सं0 पटना 645) पटना, बुधवार, 31 अगस्त 2022

सं० 2/आरोप-01-14/2018-सा0प्र0/11202  
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

6 जुलाई 2022

श्री अरूणाभ चन्द्र वर्मा (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 716/11, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, कहलगांव, भागलपुर के विरुद्ध लोक शिकायत निवारण अधिनियम, 2015 के नियम का अनुपालन नहीं करने एवं आयुक्त-सह-प्रथम अपीलीय प्राधिकार, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन नहीं करने इत्यादि आरोपों के लिए प्राप्त आरोप-पत्र में अन्तर्विष्ट आरोपों के लिए श्री वर्मा से स्पष्टीकरण की गयी।

श्री वर्मा से प्राप्त स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए उनके विरुद्ध आरोपों की वृहत जाँच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक 4266 दिनांक 26.03.2021 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक 368/स्था0 दिनांक 12.04.2022 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें आरोप सं0-01 एवं 02 को अप्रमाणित, आरोप सं0-03 को प्रमाणित तथा आरोप सं0-04 को आंशिक प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में उल्लिखित किया गया कि लोक शिकायत निवारण अधिनियम सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, जिसके अंतर्गत प्राप्त शिकायतों का निष्पादन तय सीमा के अंदर करना होता है। आरोपित पदाधिकारी द्वारा आयुक्त-सह-प्रथम अपीलीय प्राधिकार के आदेश के अनुपालन में आवश्यक तत्परता नहीं बरती गयी, जिसके कारण डेढ़ माह की अवधि में यह जानकारी नहीं प्राप्त की जा सकी कि अभिलेख गायब करने हेतु दोषी कर्मि कौन हैं। जहाँ तक श्री पवन कुमार वैश्य के द्वारा अवैध रूप से अंचल कार्यालय, कहलगाँव में वर्षों से कार्य किये जाने का प्रश्न है, इस संदर्भ में आरोपी पदाधिकारी का कहना है कि उनके गोपनीय जाँच में यह पता चला की श्री पवन कुमार वैश्य द्वारा अवैध रूप से कार्य किया जाता था। जब जाँच के क्रम में यह मामला आरोपी पदाधिकारी के संज्ञान में आ चुका था, तो उन्हें इस संदर्भ में आयुक्त-सह-प्रथम अपीलीय प्राधिकार के निदेशानुसार आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो नहीं किया गया।

जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति श्री वर्मा को उपलब्ध कराते हुए इनसे लिखित अभिकथन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। श्री वर्मा द्वारा इस संदर्भ में समर्पित लिखित अभ्यावेदन में उल्लेख किया गया कि विषयांकित मामला में भूमि सुधार उप समाहर्ता द्वारा अपने पत्रांक 1327 दिनांक 24.10.2017 से प्रतिवेदन भेजा गया। उक्त प्रतिवेदन में अभिलेख खोजने के पश्चात भी नहीं मिलने तथा वर्तमान में अभिलेख के अभिरक्ष द्वारा अभिलेख प्रभार में नहीं मिलने

तथा उनके पूर्व के प्रभारी द्वारा इन्वेंटरी में मिले दस्तावेजों के आधार पर प्रभार की जानकारी बताया गया। Inventory में उक्त अभिलेख नहीं होना बताया गया। Inventory के पूर्व अभिलेख के प्रभार में नाजिर मो० मुर्शिद थे। उनके अस्वस्थ रहने के फलस्वरूप 24.09.2014 को दण्डाधिकारी के उपस्थिति में ताला तोड़कर Inventory List बना। उक्त Inventory सूची का अवलोकन भी किया गया तथा उसमें लगान निर्धारण वाद संख्या 74/1104, 1998-99 उपलब्ध नहीं था। इसके अतिरिक्त श्री पवन कुमार वैश्य नामक व्यक्ति अंचल कार्यालय में अवैध रूप से कार्य करना को भी सही नहीं माना गया।

सम्पूर्ण विषय पर अगली तिथि 06.11.2017 के पूर्व तथ्यात्मक प्रतिवेदन पत्रांक 1556 दिनांक 02.11.2017 से आयुक्त के सचिव को भेजा गया। उक्त प्रतिवेदन में सभी तथ्यों के आधार पर अभिलेख गायब करने वाले को चिन्हित कर निलम्बन तथा प्राथमिकी जैसी कार्यवाही वगैर अग्रतर जाँच के सम्भव नहीं था। साथ ही श्री पवन कुमार वैश्य के संबंध में भी साक्ष्य के अभाव में प्रशासनिक तथा वैधानिक कार्यवाही सम्भव नहीं था।

भूमि सुधार उप समाहर्ता द्वारा स्पष्ट रूप से अनाधिकृत व्यक्ति श्री पवन कुमार वैश्य द्वारा कार्य किये जाने के विषय को गलत बताया गया है। साथ ही मात्र अपने अथवा अन्य व्यक्तियों के कार्यों से अंचल कार्यालय आते-जाते हैं का प्रतिवेदन दिया गया। इस तथ्य पर किसी प्रकार की प्रशासनिक एवं वैधानिक कार्यवाही के लिए इनके द्वारा स्वयं गोपनीय जाँच करायी गई तथा श्री पवन कुमार वैश्य, राजस्व कर्मचारी के मुंशी के रूप में कार्य करते थे की जानकारी मिली। संबंधित राजस्व कर्मचारी को किसी भी व्यक्ति से कार्य नहीं कराये जाने तथा भविष्य में प्रमाण मिलने पर प्रपत्र 'क' गठित करने की चेतावनी भी दी गई। विदित हो कि हल्का कर्मचारियों की कमी के कारण एक ही राजस्व कर्मचारी तीन-चार हल्के के प्रभार में रहते हैं तथा कार्य संपादन के लिए ग्रामीणों का सहयोग लेते हैं।

आयुक्त महोदय द्वारा अन्य वरीय पदाधिकारी उप विकास आयुक्त, भागलपुर को जाँच की जवाबदेही दी गई। जिले के अन्य वरीय पदाधिकारी किसी निष्कर्ष पर पहुँचते जो इनसे भिन्न होता तो इनका प्रशासनिक अक्षमता माना जा सकता है। इनके द्वारा दिनांक 06.11.2017 को आयुक्त महोदय के समक्ष उपस्थित होकर वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया। भूमि सुधार उप समाहर्ता का प्रतिवेदन पत्रांक 1327 दिनांक 24.10.2017 को संज्ञान में लाया गया परन्तु इनके पत्रांक 1556 दिनांक 02.11.2017 के प्रतिवेदन को मान्यता नहीं दी गई। दिनांक 06.11.2017 को आयुक्त महोदय के पूर्व के आदेशों का अनुपालन कर दिया गया था।

पत्रांक 1556 दिनांक 02.11.2017 से भेजे गये प्रतिवेदन को अमान्य किये जाने का कोई ठोस वैधानिक कारण आयुक्त द्वारा पारित आदेश में नहीं है।

श्री वर्मा से प्राप्त लिखित अभिकथन की समीक्षा प्रतिवेदित आरोप एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री वर्मा के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप लोक शिकायत निवारण अधिनियम जैसे सरकार के जन कल्याण हेतु बनाये गये अधिनियम के उल्लंघन से संबंधित है। संचालन पदाधिकारी द्वारा वृहद जाँचोपरांत श्री वर्मा के विरुद्ध आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है। लोक शिकायत से संबंधित मामलों में आयुक्त-सह-प्रथम अपीलीय प्राधिकार के आदेश के अनुपालन में श्री वर्मा द्वारा तत्परता नहीं बरती गयी जिसके फलस्वरूप मामले के निष्पादन में विलंब हुआ। श्री वर्मा को जब गोपनीय जाँच के क्रम में श्री पवन कुमार वैश्य के द्वारा अवैध रूप से अंचल कार्यालय, कहलगाँव में कार्य किये जाने से संबंधित सूचना थी, फिर भी उनके द्वारा आयुक्त-सह-प्रथम अपीलीय प्राधिकार के निदेशानुसार आवश्यक कार्रवाई नहीं की गयी। लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत सरकार द्वारा शिकायतों का निष्पादन तय समय सीमा के तहत किये जाने का प्रावधान है जिससे आम-जन के समस्याओं का निष्पादन शीघ्र किया जा सके। इस प्रकार सरकार के द्वारा जनता के शिकायतों के निवारण हेतु लागू अधिनियम का उल्लंघन श्री वर्मा द्वारा किया गया है, जो एक वरीय पदाधिकारी के लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता को दर्शाता है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक श्री अरूणाभ चन्द्र वर्मा (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 716/11, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, कहलगाँव, भागलपुर सम्प्रति उप सचिव, तकनीकी सेवा आयोग, बिहार, पटना के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के आलोक में उनके लिखित अभिकथन को अस्वीकार करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 के संगत प्रावधानों के तहत (i) निन्दन (आरोप वर्ष 2017-18) एवं (ii) असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दंड अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अरूणाभ चन्द्र वर्मा (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 716/11, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, कहलगाँव, भागलपुर सम्प्रति उप सचिव, तकनीकी सेवा आयोग, बिहार, पटना के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 में प्रावधानों के तहत निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है :-

(i) निन्दन (आरोप वर्ष 2017-18),

(ii) असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक।

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
शिवमहादेव प्रसाद,  
सरकार के अवर सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 645-571+10-डी0टी0पी0  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>